



कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी जंग कर सकती है! उसी तरह कोई किसी इंसान को बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता कर सकती है।

-रतन टाटा

जिद...सच की

वनडे के बाद टी20 में भी दबदबा कायम... 7 जंतर-मंतर पर गुस्सा, ज्ञानेश कुमार... 3 दवा कंपनियों से कमीशनखोरी... 2

शाहीन-नफीसा के बाद तीन और महिला पत्रकारों के दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप!

जंतर मंतर पर महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस पर यौन उत्पीड़न और बदसलूकी के लगाये गये आरोपों से पूरे देश में सनसनी। शहीन नफीसा की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दबाव में सरकार। एसीपी विवेक भगत को मिला एडीसीपी का चार्ज सरकार ने वापस लिया। क्राइम ब्रांच की चल रही जांच नतीजों से पहले बैकफुट पर सरकार।

» दिल्ली पुलिस पर नस्लीय भेदभाव के बाद अब लगे यौन उत्पीड़न के आरोप

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली में फिर वही कहानी लौट आयी है महिला पत्रकार, पुलिस की वर्दी और गंभीर आरोप। कुछ हफ्ते पहले शाहीन खान और नफीसा खान ने साकेत थाने के भीतर अपने साथ मारपीट और बदसलूकी की कहानी सुनाई थी। दोनों का कहना था कि उन्हें हिरासत में लेकर पीटा गया और उनकी धार्मिक पहचान सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस का व्यवहार और भी खराब हो गया। एक महिला पुलिसकर्मी को जब पता चला कि वह मुस्लिमान है तो फिर उन्हें टार्चर जैसे हालतों से गुजरना पड़ा।

इस घटना के ठीक एक महीने बाद यानि कि 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन को कवर कर रही तीन और महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस पर ऐसे गंभीर आरोप लगाये हैं कि उन आरोपों को लिखते हुए शर्म महसूस हो रही है। महिला पत्रकारों का कहना है कि कवरेज के दौरान एसीपी विवेक भगत और दूसरे पुलिसकर्मीयों ने उन्हें बेहूदा तरीके से पीछे की ओर धकेला। इस घटना के बाद पूरे देश में दिल्ली पुलिस की इस कार्यशैली पर गुस्सा और आक्रोश है, पत्रकार संगठनों ने आर-पार की लड़ाई का एलान किया है। सवाल फिर वही पुरना है कि क्या सवाल पूछने वाली महिलाओं के साथ पुलिस का रवैया महज अलग अलग घटनाओं की कहानी है या कोई बड़ा पैटर्न बनता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इसी बीच शाहीन और नफीसा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने अपने साथ मारपीट और बदसलूकी की पूरी कहानी उन्हें बताई। इसके बाद राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला और साकेत थाने का पूरा सीसीटीवी सार्वजनिक करने की मांग की।

“महिला पत्रकारों का कहना है कि कवरेज के दौरान एसीपी विवेक भगत और दूसरे पुलिसकर्मीयों ने उन्हें बेहूदा तरीके से पीछे की ओर धकेला। इस घटना के बाद पूरे देश में दिल्ली पुलिस की इस कार्यशैली पर गुस्सा और आक्रोश है पत्रकार संगठनों ने आर-पार की लड़ाई का एलान किया है।



कैसे मिल गयी बड़ी जिम्मेदारी

3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। मुद्दा था चुनावी प्रक्रिया और एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोप। प्रदर्शन के दौरान

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव हुआ। इसी दौरान तीन महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न और बदसलूकी के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस ने तीनों शिकायतों की पुष्टि की और कहा कि उन्हें निष्पक्ष जांच के लिए क्राइम ब्रांच को भेजा गया है। यानी पुलिस के खिलाफ शिकायत पुलिस की दूसरी शाखा को जांच के लिए दे दी गयी अब इस जांच का नतीजा क्या निकलता है यह आने वाला वक्त बताएगा लेकिन शिकायतों में से एक ने पूरे मामले को और बड़ा बना दिया प्रदर्शन कवर कर रही एक महिला पत्रकार ने कहा कि उसने एसीपी विवेक भगत से वहां महिला पुलिसकर्मीयों की मौजूदगी को लेकर सवाल किया। आरोप के मुताबिक इसके बाद एसपीपी ने उसके साथ अनुचित शारीरिक व्यवहार किया और उसे पीछे धकेला। उसने और बाकी की दो अन्य महिला पत्रकारों जिनके साथ भी अनुचित व्यवहार किया गया था ने इस मामले में शिकायत दर्ज की एफआईआर हुई लेकिन शिकायत के बीच अधिकारी को नयी जिम्मेदारी कैसे मिल गई? यह बड़ा सवाल है।

अक्टूबर को जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन को कवर कर रही तीन और महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस पर ऐसे गंभीर आरोप लगाये हैं

बैकफुट पर एनडीए सरकार

सरकार की तरफ से कहा गया है कि महिला पत्रकारों से उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े एक अधिकारी के अनुरोध के बाद दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपने वाले आदेश में संशोधन किया है। अपने एक्स हैडल पर जारी आधिकारिक स्पष्टीकरण के आधार पर दिल्ली सरकार ने बताया है कि 5 अक्टूबर, 2026 के एक आदेश में दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (डीएनएपीएस) के 12 अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के पद का वर्तमान कार्यभार सौंपा गया था। अब सहायक पुलिस आयुक्त विवेक भगत के संबंध में इस आदेश में

संशोधन किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन अधिकारियों को अतिरिक्त ड्यूटी का काम सौंपने का प्रस्ताव 25 अगस्त को ही शुरू कर दिया गया था यानी उन हालिया घटनाओं से काफी पहले जिनकी वजह से लोगों का ध्यान इस ओर गया। 5 अक्टूबर, 2026 को जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही इसके आदेश जारी किए गए। आदेश में बताया गया है कि वर्तमान कार्यभार सौंपना एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है। इससे संबंधित अधिकारियों को कोई आर्थिक फायदा नहीं मिलता और न ही उन्हें उस पद पर नियमित रूप से काम करने वाले अधिकारियों की तरह

कोई कानूनी जिम्मेदारी निभाने की इजाजत मिलती है। विवेक भगत ने अपनी स्वेच्छा से अनुरोध किया है कि महिला पत्रकारों के कथित उत्पीड़न के मामले में पूरी जांच होने और उसके संतोषजनक रूप से संपन्न होने तक वह वर्तमान कार्यभार की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। उनके अनुरोध को देखते हुए 5 अक्टूबर के आदेश में बदलाव किया जा रहा है और इसे केवल बाकी बचे 11 अधिकारियों के लिए फिर से जारी किया जाएगा। यह घटनाक्रम महिला पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार की खबरों के बाद दिल्ली पुलिस की बढ़ती जांच पड़ताल के बीच सामने आया है।



शाहीन और नफीसा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने अपने साथ मारपीट और बदसलूकी की पूरी कहानी उन्हें बताई।

दवा कंपनियों से कमीशनखोरी में लिप्त है भाजपा सरकार: अखिलेश

» बोले- दवाओं की कीमत बढ़ने के लिए भी कमीशन जिम्मेदार

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एकबार फिर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। सपा प्रमुख ने सरकार पर दवा कंपनियों से कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो सरकार खुद कमीशनखोरी में लिप्त हो, वह दवा कंपनियों पर कैसे शिकंजा कसेगी।

अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में कमीशनखोरी चरम पर है। महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। दवाओं की कीमत बढ़ने के लिए भी उन्होंने कमीशन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरों की झूठी बातों पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है। अखिलेश ने भाजपा पर मुकदमे हटवाने, विपक्ष पर झूठे मुकदमे लगाने और सत्ता से जुड़े लोगों को अपराध के बाद संरक्षण देने का आरोप लगाया।



डबल इंजन की आपसी टकराहट में प्रदेश पिस रहा

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की आपसी टकराहट में प्रदेश पिस रहा है। बाढ़ से प्रदेश प्रभावित है और अधिकारियों में घूसखोरी को लेकर होड़ मची है। जनता अब चुनाव का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है।

रिवरफ्रंट पर लगाएंगे रानी दुर्गावती की प्रतिमा

अखिलेश ने वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि पीडीए सरकार बनने पर रानी दुर्गावती की सोने की तलवार वाली स्वर्णिम प्रतिमा रिवरफ्रंट पर स्थापित की जाएगी।

आराधना मिश्रा ने खरगे, राहुल गांधी व प्रियंका से की मुलाकात



4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। कांग्रेस की नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने दिल लल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027, गठबंधन, संगठन की मजबूती समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बात भी की और नई जिम्मेदारी के लिए सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया।

वहीं, मोना ने बयान जारी कर प्रदेश सरकार को पेपर लीक, भर्तियों में देरी आदि के मुद्दे पर घेरा भी। उन्होंने पुलिस एसआई भर्ती, जेई भर्ती, आरओ-एआरओ भर्ती आदि की चर्चा करते हुए सरकार से सवाल किया कि भर्ती कैलेंडर समय पर क्यों नहीं चलता? पेपर लीक क्यों होते हैं? परीक्षाएं बार-बार विवादों में क्यों आती हैं? चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए वर्षों तक इंतजार क्यों करना पड़ता है? सरकार और भर्ती माफिया की कथित मिलीभगत ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब प्रदेश का युवा जवाब मांग रहा है।

आकाश आनंद की एक बार फिर बसपा में वापसी

» बसपा प्रमुख ने किया पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अपना फ़ैसला बदलते हुए कहा है कि उनके भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। यह फ़ैसला तब आया है, जब कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी में संगठनात्मक बदलाव के तहत आकाश को पार्टी के अहम पद से हटा दिया गया था।

माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स (पहले ट्विटर) पर हिंदी में किए गए एक लंबे पोस्ट में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आकाश का व्यवहार और व्यक्तित्व काफी हद तक संतोषजनक रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से पार्टी में कुछ संगठनात्मक बदलाव करने पड़े और अशोक सिद्धार्थ को राजनीति से रिटायर होना पड़ा। मायावती ने लिखा कि जैसाकि सर्वविदित है कि परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर व उनके परम अनुयायी मान्यवर श्री काशीराम जी की देश भर में बहुजन-हित हेतु जबरदस्त त्याग-तपस्या, आजीवन कड़ा संघर्ष व उनके उच्च आदर्श हमेशा ही प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, जिस पर चलकर ही बी.एस.पी. ने देश की राजनीति में अभूतपूर्व सफलताएँ अर्जित की हैं और अब खासकर आगामी यूपी विधानसभा आमचुनाव को लेकर सर्वसमाज के साथ उत्साहपूर्ण ज़बरदस्त तैयारी भी की जा रही है। यहाँ यह भी कहना है कि



मेरा निजी नहीं बल्कि पूरा 'बहुजन समाज' ही मेरा विराट परिवार है और उनका हित व कल्याण मेरे लिये सर्वोपरि है और हमेशा ही रहेगा।

इसी को मद्देनज़र रखते हुये व खासकर पार्टी में अनुशासन बनाये रखने के लिये ही मेरे द्वारा पिछले कुछ दिनों में, अनेकों सख्त फैसले भी लिये गये हैं और इसको लेकर मेरे अपने भाई-बहन व उनके परिवार के लोग कभी भी अपवाद नहीं रहे हैं, जो कि जग-जाहिर है। उन्होंने आगे लिखा कि वैसे तो आकाश आनंद का व्यक्तित्व पार्टी में काफी हद तक ठीक ही रहा है, लेकिन इनको लेकर पिछले दिनों कुछ ऐसे कारण भी रहे हैं जिसकी वजह से पार्टी संगठन में कई बार कुछ ज़रूरी परिवर्तन भी करने पड़े हैं और फिर अन्ततः आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को राजनीति से संन्यास लेने के लिए मजबूर भी होना पड़ा है। जिसके बाद से आकाश आनंद के व्यक्तित्व व कार्यशैली आदि में काफी कुछ बदलाव भी लोग देख रहे हैं, जिसका खास प्रमाण पार्टी में वापसी हेतु अभी हाल ही में सोशल मीडिया 'एक्स' पर किया गया उनका एक पोस्ट भी है, जिसकी काफी चर्चा भी है।

सीट बंटवारे के लिए सीधे सपा चीफ से करें बात: धर्मेंद्र यादव

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता धर्मेंद्र यादव ने कांग्रेस नेताओं से अपील की है कि वे सीट-शेयरिंग की मांगों पर मीडिया में चर्चा करने के बजाय सीधे स्क प्रमुख अखिलेश यादव से बात करें। धर्मेंद्र यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत की उम्मीद जताई।

उन्होंने कहा कि मैं अपने कांग्रेस सहयोगियों से कहूंगा कि जिन सीटों पर वे जीत सकते हैं, उस बारे में मीडिया में बात न करें। इसे मीडिया में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वे हमारे नेता के सामने सही तरीके से अपनी बात रखें, तो पूरा देश हमारे नेता के बारे में जानता है; वे बहुत बड़े दिल वाले नेता हैं। लेकिन मैं अपने कांग्रेस सहयोगियों से कहूंगा कि वे मीडिया में बयान देना बंद करें। सीटों के लिए कांग्रेस की मांग पर यादव ने कहा कि यह फ़ैसला सपा के शीर्ष नेतृत्व को करना है। उन्होंने कहा कि हमें कोई उलझन नहीं है। समाजवादी पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता और हर वोटर को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी का हर व्यक्ति जानता है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जो भी फ़ैसला लेंगे, वह निश्चित रूप से पार्टी के साथ-साथ पूरे उत्तर प्रदेश और



देश के हित में होगा। इसीलिए हम इन चर्चाओं में नहीं उलझ रहे हैं। यह काम कांग्रेस के लोगों ने अपने हाथ में लिया है। धर्मेंद्र यादव ने जमीनी स्तर पर चल रही तैयारियों का भी जिक्र किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश के नेतृत्व में राज्य के हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग, खासकर पीडीए मुदाय के लोग, पूरी तरह से संकल्पित हैं। लोग वोटिंग के उस पल और उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब वे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। अखिलेश यादव के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कि मुद्दा सीटों का नहीं, बल्कि जीत का है, उन्होंने बीजेपी को हराने और सरकार बदलने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक है, क्योंकि बीजेपी को हराना है, सरकार बदलनी है; देश भर के लोगों की उम्मीद,

आकांक्षा और भरोसे का केंद्र अखिलेश यादव हैं। उन्होंने आगे कहा, आने वाले 2027 में, हम जनता का ऐतिहासिक समर्थन और आशीर्वाद लेंगे और बीजेपी की बुलडोज़र सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 4 अक्टूबर, 2025 को अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि गठबंधन का मुख्य मकसद सीटों का बंटवारा नहीं, बल्कि चुनावी जीत होनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि जब लक्ष्य साफ़ हो, तो हम साथ मिलकर खड़े होते हैं; जब नज़र मजिल पर हो, तो सफ़र आसान हो जाता है! उन्होंने कहा, बड़ी बात यह नहीं है कि गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हैं या कौन सी सीट किसके पास जाती है—बड़ी बात यह है कि हम सभी यह सुनिश्चित करें कि जीत गठबंधन की ही हो। आइए फिर से दोहराएं मुद्दा सीटों का नहीं, जीत का है।

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को बड़ा संकेत दिया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, अब हमारी निगाह तीन पर नहीं, 403 पर है। उनके इस बयान को सपा के तीसरे राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर चल रही अटकलों पर विराम के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।



संगठन को बूथ स्तर पर विस्तार करेगी रालोद

» कार्यकारी अध्यक्ष ने की लखनऊ में महानगर अध्यक्षों की बैठक

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल, उत्तर प्रदेश के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में आज प्रदेश के विभिन्न महानगरों के अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के संगठन को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने, महानगर स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने तथा पार्टी की नीतियों एवं विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा जी ने कहा कि किसी भी



कार्यकर्ता तक मजबूत होना चाहिए। संगठन को केवल पदों तक सीमित न रखते हुए उसे सक्रिय, जनसरोकारों से जुड़ा और जनता के बीच निरंतर काम करने वाला संगठन बनाया जाना आवश्यक है। उन्होंने महानगर अध्यक्षों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित करें तथा स्थानीय स्तर पर

राजनीतिक दल की वास्तविक शक्ति उसका मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता होती है। राष्ट्रीय लोकदल का संगठन महानगर से लेकर वार्ड, बूथ और प्रत्येक कार्यकर्ता तक मजबूत होना चाहिए। संगठन को केवल पदों तक सीमित न रखते हुए उसे सक्रिय, जनसरोकारों से जुड़ा और जनता के बीच निरंतर काम करने वाला संगठन बनाया जाना आवश्यक है। उन्होंने महानगर अध्यक्षों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित करें तथा स्थानीय स्तर पर जनता की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए प्रभावी ढंग से आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि संगठन का विस्तार तभी सार्थक होगा, जब पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच निरंतर संवाद स्थापित करे और उनकी आवाज़ को परवाज़ दे। बैठक में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान, बूथ एवं वार्ड स्तर पर कमेटीयों के गठन, युवा एवं छात्र वर्ग की भागीदारी, महिला कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका तथा पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। महानगर अध्यक्षों से उनके क्षेत्रों में संगठन की वर्तमान स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी कार्ययोजना की जानकारी ली गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जंतर-मंतर पर गुस्सा, ज्ञानेश कुमार का आखिरी रास्ता इस्तीफा!

सुप्रीम कोर्ट में सवाल, केंद्र को देना होगा जवाब

निगाह 10 अक्टूबर पर

- » सड़क पर रिजार्ड का शोर अदालत में अधिकारों का हिसाब ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर सबसे बड़ा सस्पेंस
 - » नई दिल्ली में 110 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिये गये
 - » 15 पुलिसकर्मी घायल मुंबई में उद्धव-राज ठाकरे साथ उतरे 10 अक्टूबर को फिर दिल्ली कूच का ऐलान
- 4पीएम न्यूज नेटवर्क



नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर मुंबई की सड़कों तक सिर्फ एक शोर सुनाई दे रहा है कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो। तो दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल खड़ा है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले ऐसे फैसले ले सकते हैं जिनकी ताकत पूरे चुनाव आयोग को दी गई है और इन्हीं दो सवालों के बीच बैठे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। यानी मामला अब सिर्फ एक कुर्सी का नहीं रह गया है बल्कि मामला अब इस सवाल तक पहुंच चुका है कि चुनाव आयोग चलेगा कैसे फैसले कौन लेगा और लोकतंत्र के सबसे बड़े रेफरी की भूमिका पर उठे सवालों का जवाब कौन देगा?

10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन

काकोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन ने देशभर से लोगों के दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है यानी आंदोलन फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। दिल्ली में हिरासत और पुलिस तैनाती मुंबई में विपक्षी एकजुटता और 10 अक्टूबर के प्रस्तावित प्रदर्शन ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया है।



मुंबई में विराट गर्जना मोर्चा

मुंबई में विरोध ने अलग राजनीतिक रंग ले लिया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ सड़क पर उतरे गये हैं। दोनों नेताओं के नेतृत्व में विराट गर्जना मोर्चा निकाला गया जिसमें कांग्रेस और शरद पवार गुट की एनसीपी के नेता भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के साथ महाराष्ट्र में

जंतर-मंतर से मुंबई तक गुंजा ज्ञानेश हटाओ का नारा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली से मुंबई तक विरोध-प्रदर्शन तेज हो गया है। जंतर-मंतर पर रविवार को प्रदर्शन के दौरान करीब 110 लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात पुलिस सूत्रों ने कही है। पुलिस के मुताबिक करीब 15 पुलिसकर्मी घायल हुए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने आंदोलन को रोकने के लिए बल प्रयोग किया। दिल्ली में विरोध की वजह चुनाव आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर उठे सवाल हैं। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि मतदाता सूचियों में बदलाव से बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं और इसके लिए वह सीईसी ज्ञानेश कुमार

ज्ञानेश कुमार का क्या होगा?

एक तरफ जंतर-मंतर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और बीच में ज्ञानेश कुमार की कौसी राजनीति में आमतौर पर सड़क का फैसला और अदालत का फैसला दो अलग अलग ट्रैक लेते हैं। लेकिन इस बार दोनों ट्रैक एक ही स्टेशन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। जंतर-मंतर पर राजनीतिक और सामाजिक विरोध का दबाव बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं इन सबके बीच सीईसी ज्ञानेश कुमार के सामने मुश्किल यह नहीं कि आलोचना कितनी हो रही है। उनकी असली

मुश्किल यह है कि उठाए गए सवालों पर अदालत ने यदि कोई ठोस निर्णय दे दिया तो कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि याचिकाओं में सिर्फ बयानबाजी नहीं है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि एसआईआर से जुड़े फैसलों की जांच हो इसीआईनेट और ईआरओनेट में हुए तकनीकी बदलावों का फॉरेंसिक ऑडिट हो आयोग के रिकॉर्ड और फाइल नोटिंग सामने आए और यह तय किया जाए कि क्या ज्ञानेश कुमार ने आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल अकेले किया।

के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस ने भी रायसीना रोड से जंतर-मंतर की ओर मार्च करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों

को बैरिकेडिंग कर रोका गया। कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।

महाराष्ट्र में एसआईआर रद्द करें : उद्धव ठाकरे

शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के "हथियार" के रूप में काम करने का आरोप लगाया। वहीं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को रद्द करने की मांग की। सीईसी के खिलाफ ठाकरे बंधुओं के नेतृत्व में मुंबई में निकाले गए विरोध मार्च में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसका समापन एक रैली के रूप में हुआ। रैली में कांग्रेस नेताओं बालासाहेब थोराट और विजय वडेहीवार के अलावा शरद पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के जयंत पाटिल, शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड और अनिल देशमुख ने भी

भाग लिया। मार्च दक्षिण मुंबई स्थित मेट्रो सिनेमा से शुरू हुआ और कुछ ही दूरी तय कर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) मुख्यालय पहुंचा। प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (काँजपा) संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि शहर एक बार फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आया है। दीपके ने सभी भारतीयों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा, "अब या कभी नहीं।"



'विराट गर्जना मोर्चा' नाम से आयोजित इस प्रदर्शन में एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने या उनके इस्तीफे की मांग की गई। मार्च में राजनीतिक दलों के झंडे ले जाने की अनुमति नहीं थी और प्रतिभागियों से केवल राष्ट्रीय तिरंगा साथ रखने को कहा गया था। राज ठाकरे ने मांग की कि देश में भविष्य के चुनाव मतपत्र के जरिए कराए जाएं। उन्होंने महाराष्ट्र में एसआईआर की प्रक्रिया रद्द करने की मांग भी की। उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि अगर एसआईआर मतदाता सूची से बांग्लादेशियों को बाहर करने के लिए कराया गया था, तो सरकार ने देश में अवैध रूप से रह रहे कितने बांग्लादेशियों का पता लगाया है। महाराष्ट्र के पूर्व

मुख्यमंत्री ठाकरे ने आरोप लगाया, "ज्ञानेश कुमार भाजपा का हथियार हैं।" उन्होंने नूर्नबर्ग मुकदमों की तर्ज पर भाजपा नेताओं के खिलाफ अभियोजन की चेतावनी भी दी। उन्होंने दावा किया, "भाजपा और इन अधिकारियों को समझ लेना चाहिए कि देश में भी ऐसा ही होगा।" नूर्नबर्ग मुकदमे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों द्वारा चलाए गए सैन्य न्यायाधिकरणों की श्रृंखला थे, जिनमें एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली नाजी जर्मनी के शीर्ष अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया गया था। उद्धव ने कहा कि विपक्षी दलों की लड़ाई किसी एक पार्टी या नेता, धर्म या जाति के लिए नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए है। उन्होंने दावा किया, "भाजपा को समझ लेना चाहिए कि लोग आज शांत हैं।"

अकेले लिए गये फैसले सबसे बड़ा बम साबित हो रहे हैं

चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार को बात किसने क्या कहा किसके पास कितना अधिकार से आगे बढ़कर किसके पास क्या अधिकार था तक पहुंच चुका है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। 14 आपत्तियां के बाद अकेले लिये गये फैसले अब सबसे बड़ा बम साबित हो रहे हैं।

याचिकाओं में दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम से कम 14 मौकों पर लिखित आपत्ति या असहमति दर्ज की। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इसके बावजूद संबंधित फैसले आगे बढ़ाए गए और अब यहां फैसले कहानी

में सस्पेंस क्रिएट करते हैं अगर आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है तो फैसले की प्रक्रिया क्या थी क्या सीईसी अध्यक्ष होने के नाते अकेले निर्णय कर सकते हैं या फिर आयोग की संवैधानिक शक्ति सामूहिक निर्णय से ही चलनी चाहिए यही वह सवाल है जिसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_SanjayS

जिद... सच की

शिक्षक को योग्य के साथ संवेदनशील होना भी जरूरी

एक गांव के निजी स्कूल में पांच साल के बच्चे को स्कूल बैग न लाने पर पीटे जाने और उसका पैर टूट जाने की खबर को केवल एक शिक्षक की क्रूरता ही मान लेना उचित नहीं होगा। यह घटना एक बड़ा सवाल छोड़ती है कि आखिर बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक चुनते समय आखिर देखा क्या जाता है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी घटनाएं गाहे-बगाहे सामने आती ही रहती हैं। शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण में विषय पढ़ाने के साथ गुस्से को संभालना, बच्चों के व्यवहार को समझना, बिना हिंसा अनुशासन कायम करना और बाल अधिकारों जैसे विषय भी शामिल हों। शिक्षक का चयन सिर्फ किसी नौकरी के लिए चयन नहीं है। यह उस व्यक्ति का आकार देगा। इसलिए प्रत्येक शिक्षक की योग्यता की परीक्षा जरूरी है, लेकिन उसकी संवेदना की परीक्षा उससे कम जरूरी नहीं। हाल में विशाखापत्तनम में छह साल के बच्चे की शिक्षक द्वारा कथित पिटाई के बाद मौत का मामला भी सामने आया।

गुजरात के एक स्कूल में छात्र की पिटाई और उत्तर प्रदेश में छात्र को पीटने के बाद अभिभावक को धमकाने की घटनाएं भी सामने आईं। परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन चिंता एक ही है- जिस व्यक्ति के हाथ में बच्चे की सुरक्षा और व्यक्ति निर्माण की जिम्मेदारी है, वही कभी-कभी उसके लिए भय का कारण कैसे बन जाता है? हमारे देश में शिक्षकों की भर्ती के लिए शैक्षणिक और पेशेवर पात्रता के मानक तय हैं। सैनिक का चयन करते समय हम केवल उसकी शैक्षणिक योग्यता नहीं देखते। शारीरिक क्षमता, अनुशासन और दूसरे कई पहलुओं को परखा जाता है। फिर शिक्षक के मामले में यह मान लेने का जोखिम क्यों है कि विषय का ज्ञान और निर्धारित पात्रता उसे बच्चों के साथ व्यवहार के लिए भी तैयार कर देती है? शिक्षक का सामना रोज ऐसे बच्चों से होता है जो अलग-अलग स्वभाव, पारिवारिक परिस्थितियों और सीखने की क्षमताओं के साथ आते हैं। पांच साल का बच्चा बैग भूल सकता है, होमवर्क नहीं कर सकता, शोर कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, जिद कर सकता है। लेकिन शिक्षक की असली परीक्षा शायद यहीं से शुरू होती है। इसलिए शिक्षक चयन की प्रक्रिया पर नए सिरे से विचार जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा अपनी जगह आवश्यक है, लेकिन इनके साथ बाल मनोविज्ञान, भावनात्मक परिपक्वता, धैर्य और संवेदनशीलता को भी चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया ही जाए।

Sanjay

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

भारत को वैश्विक पूंजी युद्ध के लिए तैयार रहना होगा

टीएन निन

वैश्वीकरण से पीछे हटती दुनिया में सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही पर पहले ही कई तरह के प्रतिबंध बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर वापसी और नीतिगत दबाव के औजार के रूप में शुल्क (टैरिफ) के इस्तेमाल के बाद वैश्विक स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को भी झटका लगना तय है। इसके बाद अगला कदम अमीर देशों की ओर से पूंजी की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही पर प्रतिबंधों के रूप में सामने आ सकता है। विकासशील देशों में पूंजी नियंत्रण लंबे समय से सामान्य बात रही है। इस तरह के बड़े बदलाव की प्राथमिक वजह अमेरिका में दिखाई दे रही है, जहां कंपनियों की बढ़ती कर्ज जरूरत और अमेरिका के बजट घाटे के बीच टकराव बढ़ रहा है। तकनीक और कृत्रिम मेधा (एआई) की दौड़ में आगे चल रही बड़ी कंपनियां कुछ समय पहले तक अपने पूंजीगत खर्च की जरूरतें अपनी कमाई से पूरी कर रही थीं।

अब ऐसा नहीं है। निवेश योजनाओं में भारी विस्तार के कारण ये कंपनियां बाजार से बड़ी मात्रा में कर्ज उठा रही हैं। अमेरिका में कॉरपोरेट बॉन्ड जारी किए जाने की मात्रा दो वर्षों में 80 प्रतिशत बढ़ गई है। दूसरी ओर, संघीय बजट घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7 प्रतिशत तक पहुंच गया है और इसके जल्द नियंत्रित होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे। अमेरिका की घरेलू बचत इन बढ़ती पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका दशकों से दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश बना हुआ है। लेकिन विदेशों से पूंजी की उसकी बढ़ती जरूरत ऐसे समय में सामने आ रही है, जब लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिकी प्रतिभूतियों से दूरी बना रही हैं। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी प्रतिभूतियों में अपनी हिस्सेदारी आधी कर दी है, जबकि अब अमेरिकी

प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक जापान भी इससे दूरी बनाना शुरू कर चुका है। बाजार में कारोबार योग्य अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 2015 में 50 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 30 प्रतिशत रह गई है। केंद्रीय बैंक जहां अपने डॉलर भंडार में कटौती कर रहे हैं, वहीं उन्होंने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाई है।

पिछले साल सोने ने अमेरिकी सरकारी बॉन्ड को पीछे छोड़ते हुए केंद्रीय बैंकों की रिजर्व परिसंपत्तियों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली। एक साल में सोने की कीमत 25 प्रतिशत बढ़ चुकी है और भारतीय अब भी सोने

सकता है। इससे बाजार में अधिक पैसा आने के कारण महंगाई बढ़ सकती है और वास्तविक यानी महंगाई-समायोजित अर्थों में उसके कर्ज का बोझ कम हो सकता है। भारत दशकों से ऐसा करता रहा है। वास्तव में, पश्चिमी देशों का कर्ज बढ़ने के साथ पिछले पांच वर्षों में अमेरिका में महंगाई पिछले दशक की तुलना में दोगुने से अधिक, यूरोप में तीन गुना और जापान में पांच गुना अधिक रही है। इसे कर्ज के बोझ को नियंत्रित करने के लिए छेड़े गए महंगाई युद्ध के रूप में देखा जा सकता है। एक और संभावना है—हालांकि अभी यह दूर की बात लगती है, लेकिन पूरी तरह असंभव नहीं है—कि अमेरिका व्यापार की तरह



के बड़े खरीदारों में शामिल हैं। अमेरिकी डॉलर में बढ़ते कर्ज और इस कर्ज को लेकर घटती वैश्विक मांग के बीच इसका स्वाभाविक असर ब्याज दरों पर पड़ा है। अमेरिकी ट्रेजरी की ब्याज दरें अब दो दशकों के उच्चतम स्तर पर हैं और लगातार बढ़ रही हैं। इसके बावजूद नए अमेरिकी कर्ज की नीलामी में अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की हिस्सेदारी पहले के मुकाबले कम हो गई है। पांच साल की ट्रेजरी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर महज एक महीने में 0.64 प्रतिशत बढ़ गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट पिछले कुछ सप्ताह से बाजार को शांत करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं हुआ है। अगर ऊंची ब्याज दरों के बावजूद अमेरिका को दूसरे देशों से अपनी जरूरत के मुताबिक पूंजी नहीं मिलती है तो वह डॉलर की आपूर्ति बढ़ा

पूंजी के मामले में भी दबाव की नीति अपना सकता है। ट्रंप पहले ही कुछ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में निवेश प्रतिबद्धताओं को शामिल कर चुके हैं। आज वह पूंजी के प्रवाह को अमेरिका में आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कल पूंजी के बाहर जाने पर भी अंकुश लगाया जा सकता है।

इस आशंका को देखते हुए कुछ देशों ने रक्षात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नीदरलैंड ने पिछले कुछ महीनों में न्यूयॉर्क से 78 टन सोना लंदन स्थानांतरित किया है। इसके पीछे संभावित 'भूराजनीतिक अस्थिरता' को कारण बताया गया है। इससे कुछ समय पहले फ्रांस ने भी अमेरिका में रखा अपना पूरा सोना वापस निकाल लिया था। जर्मनी में भी ऐसा ही करने की मांग उठ रही है। कुछ समय पहले तक जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी।

पुष्परंजन

जिस शेख हसीना ने फिश डिप्लोमेसी की शुरुआत की थी, वो अब राजनीति के जल से बाहर हैं। हिलसा बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। स्थानीय लोग इसे इलिश कहते हैं। स्वाद में बेजोड़ होने की वजह से इसे मछलियों की रानी भी माना जाता है। इलिश के बगैर 'एई पार बांग्ला या ओई पार बांग्ला' की जनता रह नहीं सकती। बीते 26 सितंबर 2026 को दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन में हिलसा फेस्टिवल आयोजित हुआ था, जिसमें कुछ वरिष्ठ राजनेता, राजनयिक, पत्रकार, शिक्षाविद् और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हुईं। उस हिलसा फेस्टिवल में तबे पर हिलसा फ्राई का मेहमानों ते लुत्फ उठाया। चाणक्यपुरी स्थित दूतावास के मैत्री ऑडिटोरियम में आयोजित इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य फूड एवं कलिनरी डिप्लोमेसी के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करना था। इस अवसर पर ढाका से प्रकाशित एक विशेष पुस्तक 'ए फिश कॉल्ड इलिश' का विमोचन भी भारतीय हस्तियों द्वारा किया गया।

उत्सव में आए मेहमानों को हिलसा मछली से बने विभिन्न प्रकार के पारंपरिक बंगाली व्यंजन, जैसे सरसों हिलसा, फ्राइड हिलसा आदि, के साथ-साथ पारंपरिक बांग्लादेशी भोजन परोसा गया। बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम. रियाज हामिदुल्लाह ने इस अवसर पर कहा कि हिलसा सिर्फ एक मछली नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश की पहचान, समाज और अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ी हुई है। यह आयोजन ऐसे समय में किया गया, जब दोनों देशों के बीच हिलसा के व्यापारिक समीकरणों को लेकर कई कूटनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। वर्ष 1991

पानी के लिए बांग्लादेश की 'हिलसा' कूटनीति



के बाद से बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों में उतार-चढ़ाव इन दोनों देशों के राजनेताओं के सत्ता में आने-जाने के साथ बदलते रहे हैं। शायद किसी को याद हो कि 19 मार्च 1998 को बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश के तत्कालीन विदेश मंत्री आनन-फानन में नई दिल्ली पहुंचे थे।

यह भूलकर कि पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देश का स्थायी हित महत्वपूर्ण है। उन दिनों शेख हसीना सत्ता में थीं। 16 मई से 1 जून 1996 तक अटल बिहारी वाजपेयी की 16 दिनों की पहली टर्म वाली सरकार को उन्होंने हल्के में लिया था। भारत में कई लोग ऐसा मानते हैं कि 1971 में भारत ने जो कुर्बानी दी थी, बांग्लादेश ने उसके लिए पर्याप्त आभार नहीं जताया। शायद ही कोई इस बात से इनकार करेगा कि भारत में चार पार्टियों वाली समावेशी सरकार के समय दोनों देशों के रिश्ते बहुत निचले स्तर पर थे। उस दौरान विदेश मंत्री स्तर की किसी द्विपक्षीय यात्रा की बात तो दूर, सरकार प्रमुख की यात्रा तक नहीं हुई थी। केंद्र में सत्ता मजबूत होती है, तो रिश्ते भी बदलते हैं। शेख हसीना, 'जैसी बही

बयार, पीठ तब तैसी कीजिए', वाली राजनेता रही हैं। दक्षिण एशिया में 'हिलसा डिप्लोमेसी' की शुरुआत 1996 में सद्भावना और सहयोग के इरादे से हुई थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1996 की ऐतिहासिक गंगा जल बंटवारा संधि से ठीक पहले, सद्भावना के एक सोचे-समझे कदम के तौर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु को हिलसा मछली की एक खेप भेजी थी। 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके भारतीय समकक्ष एच. डी. देवेगौड़ा के बीच हुई 30 साल की इस संधि ने जनवरी-मई के सूखे मौसम के दौरान गंगा के पानी के बंटवारे का एक ढांचा तैयार किया था।

इस दौरान नदी का बहाव काफी कम हो जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई गंगा जल संधि 11 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है। वर्ष 1996 के बाद उभयपक्षीय परिस्थितियां काफी बदली हैं। आबादी बढ़ी है, पानी की जरूरत बढ़ी है और नदी तथा मौसम से जुड़ी परिस्थितियों को लेकर भी नई चुनौतियां सामने आई हैं। नई संधि होती है, तो भारत और

बांग्लादेश की जरूरतों के साथ-साथ भारत के अंदर अलग-अलग राज्यों की पानी से जुड़ी जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा। गंगा नदी बांग्लादेश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश का लगभग 37 प्रतिशत भू-भाग, जो चार डिवीजनों के 26 जिलों और 163 उप-जिलों में फैला है, इस नदी पर निर्भर है, जिसे बांग्लादेश में 'पद्मा' के नाम से जाना जाता है। अब आने वाले दशकों के लिए ढाका और नई दिल्ली को एक नई व्यवस्था तैयार करनी होगी। तीस्ता जल बंटवारे में हुई उठा-पटक की कहानी अलग है। तीस्ता नदी के लिए पानी के बंटवारे की एक अलग व्यवस्था को 2011 में बांग्लादेश और भारत ने अंतिम रूप दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के बाद उस पर कभी हस्ताक्षर नहीं हो सके।

पद संभालने के बाद मुहम्मद यूनस की अंतरिम सरकार ने शुरू में भारत को हिलसा का एक्सपोर्ट रोक दिया था। हालांकि, बाद में यह फैसला बदल दिया गया और 21 सितंबर 2024 को वाणिज्य मंत्रालय ने भारत को 3,000 टन हिलसा एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी। 2025 में 2,420 टन हिलसा भारत निर्यात करने की मंजूरी दी गई थी। 2026 में इसे आधा घटाकर 1,200 टन कर दिया गया है। हिलसा के कम-ज्यादा एक्सपोर्ट से ढाका-नई दिल्ली के बनते-बिगड़ते कूटनीतिक संबंधों को हम नाप सकते हैं। नई सरकार के गठन के बाद भी बांग्लादेश चैन से नहीं है। ऐन दुर्गा पूजा के समय भारत निर्यात होने वाली हिलसा मछली मुद्दा बनती है। हालांकि, बंगाली आबादी हिलसा को अपनी खान-पान की संस्कृति का अहम हिस्सा मानती है, लेकिन बांग्लादेश में इसे लेकर चिंताएं भी हैं।

लीवर

हेपेटाइटिस बी से बचाव

हेपेटाइटिस बी के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध है। यह संक्रमण रक्त और शरीर के संक्रमित द्रवों के संपर्क से फैल सकता है। सुरक्षित चिकित्सा प्रक्रियाएं, संक्रमित रक्त से बचाव और आवश्यक होने पर टीकाकरण महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हैं। बता दें लीवर की बीमारी हमेशा दर्द के साथ शुरू होती है। लेकिन कई लीवर रोग शुरुआती चरण में स्पष्ट लक्षण नहीं देते।

लक्षण

त्वचा या आंखों का पीला पड़ना, गहरे रंग का पेशाब, लगातार थकान, भूख कम होना, मतली या पेट में दर्द कुछ लीवर रोगों में हो सकते हैं। लेकिन इन लक्षणों के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसलिए लक्षण देखकर स्वयं बीमारी तय करने के बजाय चिकित्सकीय जांच कराना बेहतर है।

हेपेटाइटिस सी की चुनौती

हेपेटाइटिस सी मुख्य रूप से संक्रमित रक्त के संपर्क से फैलता है। इसका कोई प्रभावी टीका अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आधुनिक एंटीवायरल उपचार से अधिकांश संक्रमित लोगों को ठीक किया जा सकता है। इसलिए जोखिम वाले लोगों में समय पर जांच बेहद महत्वपूर्ण है।

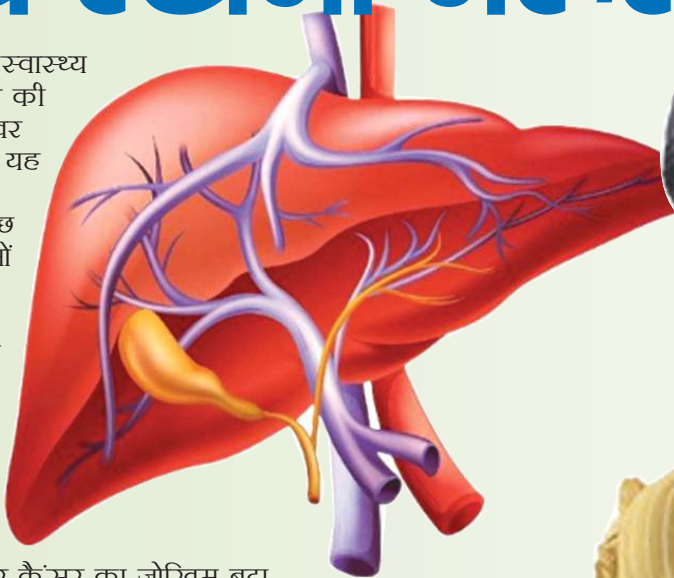


शराब और लीवर

शराब का अत्यधिक सेवन लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उनके लिए सेवन कम करना या बंद करना स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यदि शराब छोड़ने में कठिनाई हो तो चिकित्सकीय सहायता लेना उपयोगी है। बता दें डिटॉक्स ड्रिंक लीवर को साफ कर देती है। शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं में लीवर स्वयं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसी विशेष डिटॉक्स उत्पाद को इलाज मानना उचित नहीं है।

को स्वस्थ रखना जरूरी

हम अपने हृदय, फेफड़े और दिमाग के स्वास्थ्य पर अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन लीवर की ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान जाता है। लीवर शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह पोषक तत्वों के प्रसंस्करण, कई रासायनिक प्रक्रियाओं और शरीर से कुछ अपशिष्ट पदार्थों को हटाने जैसी प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। लीवर से जुड़ी समस्याओं की खास चुनौती यह है कि कई स्थितियों में शुरुआती चरण में स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। हेपेटाइटिस का अर्थ लीवर में सूजन है। वायरल हेपेटाइटिस के प्रमुख प्रकार ए, बी, सी, डी और ई हैं। इनमें हेपेटाइटिस बी और सी लंबे समय तक रहने वाली बीमारी का कारण बन सकते हैं और समय के साथ लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर का जोखिम बढ़ा सकते हैं।



मनीष कुमार मौर्य

बिना सलाह दवा न लें

कई लोग दर्द या दूसरी सामान्य परेशानी में बिना चिकित्सकीय सलाह के लंबे समय तक दवा या सप्लीमेंट लेते रहते हैं। हर दवा हर व्यक्ति के लिए समान रूप से सुरक्षित नहीं होती। इसलिए नियमित या लंबे समय तक दवा लेने से पहले चिकित्सकीय सलाह जरूरी है।



फैटी लीवर और जीवनशैली

लीवर से जुड़ी एक अन्य आम चर्चा फैटी लीवर को लेकर है। शरीर का अधिक वजन, मेटाबोलिक समस्याएं और कुछ अन्य कारक लीवर में अतिरिक्त वसा जमा होने से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे मामलों में संतुलित भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि और चिकित्सकीय सलाह महत्वपूर्ण हो सकती है।

हंसना मजा है

पत्नी- मैं तो तंग आ गई हूँ इस आदमी से, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता... पति - अरे भाग्यवान, अब क्या खता हो गई मुझसे... पत्नी - ये कल तुमने गैस खत्म होने पर कैसा सिलिंडर लगाया है, दो बार दूध गर्म किया, दोनों बार ही फट गया...

पत्नी - शादी से पहले तो तुम कहते थे कि शादी के बाद मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करूंगा... अब क्या हुआ? पति - सच बताऊं जानू... पत्नी (खुश होते हुए) - हां बताओ... पति - मुझे नहीं लगता था कि हमारी शादी हो ही जाएगी...

आज का महाज्ञान... जिस पुरुष ने आज के समय में बीवी, नौकरी और स्मार्टफोन के बीच में सामंजस्य बैठा लिया हो, वह पुरुष नहीं महापुरुष कहलाता है...

रेलवे पूछताछ केंद्र पर एक महिला पहुंची... क्लर्क - कोहरे के कारण सब ट्रेनें लेट हैं, और कुछ पूछना है... महिला - इस ट्रेस में मैं मोटी तो नहीं लग रही...

पप्पू - मां ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं... मां - बेटा इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगी किसी को तू... पप्पू बोला- कसम से आज पहली बार देवता वाली फीलिंग आ रही है...

कहानी

बुद्ध, आम और बच्चे

बात उस समय की है जब महात्मा गौतम बुद्ध एक आम के बगीचे में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां खेलते हुए बच्चों की एक टोली आ गयी। सभी बच्चे आम का बगीचा देख कर, आम तोड़ने के लिए वहीं रुक गये। बच्चों ने आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर मरना शुरू किया। देखते ही देखते जमीन पर आमों का ढेर लग गया। इतने में एक बच्चे ने थोड़े ऊंचे आम को तोड़ने के लिए एक पत्थर ज्यादा तेज फेंका। वह पत्थर विश्राम कर रहे महात्मा जी को जा कर लगा और उनके माथे से खून आने लगा। सभी बच्चे यह देख कर बहुत डर गए। उन्हें लगा अब तो बुद्ध जी उनको बहुत डांटेंगे। तभी उनमें से एक बालक डरता हुआ महात्मा जी के पास गया और उनसे हाथ जोड़ते हुए बोला, हे महात्मा! हमसे बहुत बड़ी गलती हो गयी है। हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी वजह से आपको यह पत्थर लग गया और आपके माथे से खून आ गया। इस बात को सुन कर, महात्मा बुद्ध ने बच्चों से कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे पत्थर लगा। पर दुख इस बात का है कि पेड़ को पत्थर मारने से पेड़ तुम्हें मीठे फल देता है। लेकिन मुझे पत्थर मारने से तुम्हें डर मिला। इस तरह अपनी बात पूरी कर के महात्मा जी आगे चल दिए। और बच्चे भी आम बटोर कर वापस अपने अपने घर चले गए।

कहानी से सीख: इस कहानी के माध्यम से महात्मा गौतम बुद्ध हमें बताना चाहते हैं कि, कोई अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तब भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ को पत्थर मारने पर भी वह बदले में मीठे फल ही देता है उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए।

7 अंतर खोजें



जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951



पंडित संदीप आनंद शर्मा

मेष 	कार्यस्थल पर काम का दबाव हो सकता है, योजनाबद्ध रहें। व्यापार में लेनदेन को लेकर सजग रहने की जरूरत है। पारिवारिक विवादों को बातचीत से हल करें।	तुला 	कार्यक्षेत्र में आपके विचार सराहे जाएंगे। व्यापार में धन लाभ होगा, नए अवसर मिलेंगे। परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा। बचत बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे।
वृषभ 	नौकरी में बदलाव के अवसर आ सकते हैं, दिन अनुकूल है। व्यापार में साझेदारी से बड़ा फायदा होने की संभावना है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रसन्नता रहेगी।	वृश्चिक 	करियर में नए अवसर मिलेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। निजी संबंधों में मिठास और विश्वास बढ़ेगा।
मिथुन 	कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। व्यापार में शत्रुओं पर आपकी विजय होगी। परिवार का सहयोग आपकी हिम्मत बढ़ाएगा। रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग है।	धनु 	कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचें, कामजात जांचें। व्यापार में सोच-समझकर ही निवेश करें। पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं। अनावश्यक धन हानि से बचें।
कर्क 	रचनात्मक काम में सफलता मिलेगी, मन लगाकर काम करें। व्यापार में नई रणनीति से मुनाफा बढ़ेगा। संतान की सफलता से गर्व महसूस होगा।	मकर 	नौकरी में सहकर्मियों के सहयोग से काम पूरे होंगे। व्यापार में जबरदस्त लाभ के योग बन रहे हैं। मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।
सिंह 	कार्यस्थल पर संयम बनाए रखें, गुस्सा न करें। व्यापारिक निर्णय सोच-समझकर ही लें। घरेलू सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलन आवश्यक है।	कुम्भ 	कार्यस्थल पर आपका दबदबा बढ़ेगा, तरक्की मिलेगी। व्यापार में बड़ा अनुबंध हाथ लग सकता है। परिवार में आपकी सलाह को माना जाएगा। फुर्ती बनी रहेगी।
कन्या 	आपकी कार्यक्षमता से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे। व्यापार में छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी। पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।	मीन 	भाग्य का सहयोग मिलेगा, काम आसानी से पूरे होंगे। व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी। धार्मिक झुकाव बढ़ेगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी।

आईटी की छापेमारी पर भड़की रकुल प्रीत सिंह मेरा किसी विदेशी लेनदेन से कोई लेना देना नहीं

रकुल प्रीत सिंह और उनके ससुर वासु भगनानी बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में हैं। दरअसल, टैक्स चोरी और फिल्मों के नाम पर विदेशों में पैसे भेजने के मामले में उनका नाम सामने आया था, जिसके सिलसिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी भी की थी। अब रकुल प्रीत सिंह ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है।

रकुल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर करके सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो बीते कई सालों से रेगुलरली टैक्स भर रही हैं और उनका किसी भी विदेशी लेन-देन से ताल्लुक नहीं है। एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा- यह काफी दुखद है कि खुद को रिपोर्टर कहने वाले और कुछ मैनस्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों में बिना फैक्ट्स चेक किए ही खबरों को सनसनीखेज बनाकर पेश करने का चलन बढ़ता जा रहा है।

इसलिए हमेशा के लिए सच साफ बता देती हूँ। वो रेड यानी तलाशी मुझसे जुड़ी हुई नहीं थी। यह बात सब जान लें कि मैं आर्मड फोर्सेस बैंकग्राउंड से हूँ और इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। मैं कड़ी मेहनत से आगे आई हूँ और एक जिम्मेदार, कानून मानने वाली नागरिक के तौर पर 20 साल की उम्र से अपना टैक्स भर रही हूँ। रकुल ने अपनी सफाई देते हुए आगे कहा कि वो किसी भी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से किसी भी तरह के गैर-कानूनी विदेशी लेन-देन का हिस्सा नहीं हैं। रकुल बोलीं- मैं यह भी कहना चाहूंगी कि देश या विदेश में कहीं भी मेरे पास किसी की कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। न ही कभी किसी ने मुझे कोई

रकुल ने की खास अपील

मीडिया संस्थानों से अपने पोर्टल से गलत जानकारी वाली खबरें हटाने की अपील करते हुए रकुल ने कहा- मैं उन सभी से गुजारिश करती हूँ, जिन्होंने ये झूठी और मनगढ़ंत खबरें छपी हैं, वो इन्हें तुरंत हटा लें और सही फैक्ट्स सामने लाएं। मैं समझती हूँ कि मीडिया बिजनेस चलाने वालों पर कर्माधिकार प्रेशर होता है, लेकिन यह सब फैक्ट्स की कीमत पर नहीं हो सकता। किसी दूसरे की इमेज या रोजी-रोटी की कीमत पर तो बिल्कुल भी नहीं। रकुल प्रीत सिंह की बात करें तो वो जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में शूर्पणखा के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म में रणवीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में दिखाई देंगे। यह फिल्म दीवाली 2026 के मौके पर रिलीज होगी।

प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी है और न ही मैं सिद्धांतों के तौर पर ऐसे महंगे तोहफे स्वीकार करती हूँ।

अनमोल टीवी शो हमारी राधा में दिवस्ट, फैस ने सेट पर किया प्रदर्शन

जीके FTA चैनल अनमोल टीवी के पहले ओरिजिनल फिक्शन शो हमारी राधा ने दर्शकों के बीच जबरदस्त पकड़ बना ली है। शो में राधा (सिमरन कौर) अपने पति गिरधर (अक्षय म्हात्रे) पर अटूट भरोसा करती है, जबकि गिरधर शनाया (वैदेही नायर) के साथ उसे धोखा दे रहा है। इसी ट्रैक से आहत होकर शो के जुनूनी प्रशंसक शूटिंग सेट पर पहुंच गए और गिरधर के खिलाफ प्रदर्शन किया। फैस ने मांग की कि राधा को सच्चाई बताई जाए। एक प्रशंसक ने कहा, राधा को धोखा खाते देखना दुखद है, वह इससे बेहतर की हकदार है। सिमरन कौर ने कहा कि दर्शकों का यह प्यार खास है, आगे कहानी में बड़ा मोड़ आने वाला है। वहीं अक्षय म्हात्रे ने कहा कि गिरधर में कई कमियां हैं, ऐसा निगेटिव किरदार निभाना चुनौतीपूर्ण है। अब सवाल है कि सच्चाई सामने आने पर राधा क्या करेगी?

देखें हमारी राधा हर दिन रात 9.30 बजे, सिर्फ अनमोल टीवी पर।



ऋचा चड्ढा 2026 को नहीं मान रही हैं कंटेंट सिनेमा का साल

हनुमान अंश को जल्द सिनेमाघरों में दो महीने पूरे होने वाले हैं। इन दो महीनों में यह फिल्म भारत में 300 करोड़ से ज्यादा और वर्ल्डवाइड 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। अब इसकी सक्सेस पर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने अपनी राय दी है। एक्ट्रेस का मानना है कि साल 2026 को कंटेंट आधारित सिनेमा के लिए बड़ा साल कहना अभी जल्दबाजी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि ये निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में दर्शकों की पसंद में कोई बड़ा बदलाव आया है। अभिनेत्री ने 2026 को कंटेंट के लिए लैंडमार्क साल मानने की बात से असहमति जताई। ऋचा ने कहा, अगर यह हनुमान अंश के संदर्भ में है, तो वह अलग बात है। इस साल और क्या चला है... ऑब्सेशन हॉलीवुड की फिल्म है, इसलिए हम उसकी तुलना अपनी फिल्मों से नहीं कर सकते। ऋचा ने आगे कहा, पौराणिक फिल्में वैसे भी अच्छा करती हैं। धार्मिक या पौराणिक चीजें सभी के लिए सुरक्षित होती हैं। ये

तो लोग देखते ही हैं। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे लगता है कि बेहतर स्क्रिप्ट और लेखकों को ज्यादा पैसे देने से हम उस दौर में पहुंच सकते हैं, जहां कंटेंट आधारित सिनेमा सबसे आगे होगा। फिल्म का निर्देश विशाल चतुर्वेदी ने किया है। फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपये था और इसने पहले दिन 10 लाख का बिजनेस किया। तीसरे हफ्ते फिल्म के कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली। अब 59 दिनों में इस फिल्म ने भारत में नेट 324.73 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है।



रणवीर कपूर की फिल्म रामायण का पहला पार्ट रिलीज होने वाला है।

मगर उससे कुछ वक्त पहले ही सेट पर एक बड़ा हादसा हुआ। रामायण के सेट पर आग लगने की जानकारी सामने आई

रामायण के सेट पर लगी आग, मची अफरा-तफरी



है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी वायरल हुए हैं। राहत की बात ये है कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस घटना की जानकारी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने भी दी। FWICE के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी ने पुष्टि की है कि रणवीर कपूर की फिल्म रामायण के सेट

पर आग लग गई थी। उन्होंने इंडिया टुडे/आजतक को बताया कि ये एक छोटी सी घटना थी। स्टूडियो के बाहर लगे एक टेंट में आग लगी थी। हालांकि, आग को समय रहते काबू में कर लिया गया और इसे फैलने से रोक लिया गया। इस वजह से सेट पर मौजूद किसी भी शख्स को कोई खतरा नहीं हुआ। बीएन तिवारी ने कहा- कुछ दिन पहले भी पास की एक जगह पर आग लगने की घटना हुई थी। इसके बाद मैंने सभी प्रोड्यूसर्स से बात कर उन्हें सेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए कहा था। लेकिन लापरवाही की वजह से रामायण के सेट पर फिर आग लग गई। अच्छी बात ये रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई और नुकसान भी ज्यादा नहीं हुआ।

उम्र के साथ मेरे अंदर ठहराव व आत्मविश्वास आया है : अजय देवगन

अजय देवगन की फिल्मी पारी में एक्शन का खास मुकाम रहा है। 'सिंघम' से लेकर कई फिल्मों में वह पर्दे पर धुआंधार स्टंट करते नजर आए हैं। लेकिन अब 57 साल की उम्र में खुद अजय मानते हैं कि शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। 'दृश्यम 3' में भले ही वह एक्शन अवतार में नजर नहीं आ रहे हों, लेकिन इस फिल्म के दौरान उन्हें अपनी उम्र और पुराने स्टंट्स का असर जरूर महसूस हुआ। अजय देवगन ने बातचीत में अपनी उम्र और शरीर पर पड़ रहे पुराने स्टंट्स के असर को लेकर बेबाकी से बात की। उन्होंने कहा कि उम्र के साथ उनके अंदर ठहराव और आत्मविश्वास आया



है। यही वजह है कि अब वह किरदारों को पहले से थोड़ा अलग तरीके से निभाते हैं। अजय ने कहा- मुझे भले ही एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता रहा हो। इस फिल्म में भले ही मैंने एक्शन नहीं किया हो, लेकिन उम्र के साथ एक ठहराव और आत्मविश्वास आया है। इसलिए किरदार वही है, लेकिन उसे निभाने का तरीका थोड़ा अलग महसूस हो सकता है।

राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने लगायी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में निजी फर्म का बकाया भुगतान करने के अपने ही हलफनामे का पालन न करने पर अभिनेता राजपाल यादव को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभिनेता का अहंकार सही जगह पर लाने की जरूरत है और उनकी असली जगह जेल में है। सीजेआइ सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि 15 सितंबर को अभिनेता को दो सप्ताह का आखिरी मौका दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दो करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा (पांच अक्टूबर) बीत जाने के बाद भी कोई भुगतान नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान जब राजपाल यादव के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता गरीब नहीं हैं, तो जस्टिस बागची मड़क उठे। उन्होंने टिप्पणी की कि वे आपसे अधिक अमीर हो सकते हैं, लेकिन आपने जितनी राशि हड़पी है, उस हद तक वे पीड़ित हैं।



पंजाब सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप, मचा सियासी बवाल

» हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। पंजाब सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जिसको लेकर सियासत गरमा गई है। भाजपा, अकाली दल व कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष आप सरकार व सीएम भगवंत मान को घेरा लिया है। इस बीच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबी सहयोगियों के खिलाफ ईडी के आरोपों की सीबीआई जांच कराने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था।

दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पंजाब के पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्रों से जुड़े मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का मान सरकार पर वार

जांच निष्पक्ष और समय सीमा में होनी चाहिए: परगट सिंह

पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष परगट सिंह ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। परगट सिंह ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में माननीय



उच्च न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। अब जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तय समय सीमा में होनी चाहिए। इसमें कोई देरी, राजनीतिक दबाव या जांच को कमजोर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

ये है पूरा मामला

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने के हाईकोर्ट ऑर्डर पर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री के एक विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) समेत पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने आदेश दिया। अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से साझा किए गए दस्तावेज प्रथम दृष्टया उनके भ्रष्टाचार में लिप्त होने के संकेत देते हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर अब आम आदमी पार्टी ने अहम अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस बीच विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए भ्रष्टाचार को कतई बदतर नहीं करने की उसकी नीति पर सवाल उठाए।

न किए जाने के बाद हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की गई थी। आप ने बताया कि पंजाब सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

बीजेपी की भजन सरकार से नाराज हैं अन्नदाता : गहलोत

» राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री बोले- पंचायत चुनाव में सबक सिखाएंगे किसान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों की आहट के बीच राज्य की राजनीति गरमा गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हलिया बयान पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान और गरीब वर्ग आगामी पंचायत चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करारा सबक सिखाएंगे। गहलोत ने मुख्यमंत्री के बयान की कड़ी आलोचना की। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि किसान केवल 20-25 दिन ही काम करते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने इस टिप्पणी को जुमला बताते हुए कहा कि देश के अन्नदाता को लेकर मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि दिन-रात कड़ी मेहनत करने वाले किसानों के योगदान को इस तरह कम आंकना सही नहीं है। सरकार ने अन्नदाता का अपमान करके किसानों को नाराज किया है। गहलोत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के बयान और भाजपा सरकार की नीतियों से त्रस्त होकर राज्य का किसान तथा गरीब वर्ग अब चुनाव के जरिये अपना जवाब देगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान की किसानों में तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। उन्होंने पूरा विश्वास जताया कि आगामी पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी।



भाजपा के राज्यसभा के आठ उम्मीदवारों ने किया नामांकन

» ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषित आठों उम्मीदवार मंगलवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। उम्मीदवारों के पहुंचते ही भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ सभी प्रत्याशियों का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने आज नामांकन भरा। भाजपा ने सोमवार को यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आठ उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे।

भाजपा के आठ उम्मीदवारों में धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं। प्रदेश मुख्यालय पर स्वागत कार्यक्रम के बाद सभी उम्मीदवार विधानसभा के लिए रवाना होंगे। यहां वे राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा।

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है। भाजपा ने फिलहाल आठ उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवाणी पहले ही नामांकन कर चुके हैं। भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर पार्टी कार्यालय से विधानसभा तक कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

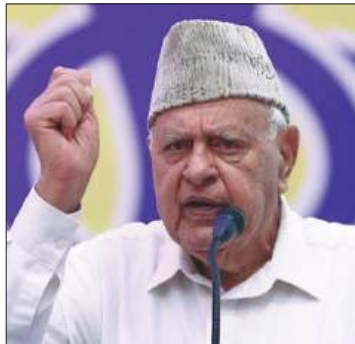
ईसी को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस पर खुशी

» नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बोले-वो मामले को देखेगा और गलतियों को सुधारेगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव आयुक्त के फैसलों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि शीर्ष अदालत ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने यह बात पार्टी की एक बैठक के बाद कही। श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय के बाहर मीडिया के साथ बातचीत में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बिना फैसले लिए, मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया।

हमें उम्मीद है कि वो मामले को देखेगा और गलतियों को सुधारेगा। उन्होंने आगे बताया कि यह बैठक संगठन को मजबूत



करने और उन कमियों की पहचान करने के लिए बुलाई गई थी जिन्हें दूर करने की जरूरत है। पूर्व सीएम ने कहा, यह बैठक पार्टी को मजबूत करने के लिए बुलाई गई थी। उन्होंने बताया कि श्रीनगर के आठ विधायकों, वार्ड अध्यक्षों और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की गई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमने उनसे उन कमियों के बारे में बात की जिन्हें दूर करने

चुनाव आयोग स्वायत्त होता तो आज ऐसी हालत नहीं होती

इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने सीईसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े मौजूदा विवाद पर पूछे गए सवाल पर कहा था, सबसे बड़ी गलती जवाहरलाल नेहरू के प्रशासन ने की थी। चुनाव आयोग को पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए था, आज वो हम मुगल रहे हैं। अगर चुनाव आयोग स्वायत्त होता तो आज ऐसी हालत नहीं होती।

की जरूरत है। पार्टी के नए संविधान के बारे में उन्होंने कहा कि जरूरी आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही इसे जनता के सामने पेश किया जाएगा।

उन्होंने कहा, सबसे पहले, हम इसे अपनी कार्यसमिति के सामने रखेंगे। इसके मंजूर होने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जम्मू-कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस का दोतरफा फोकस है - संगठन में बदलाव और चुनाव आयोग से जुड़ी कानूनी कार्यवाही में शामिल होना।

दिल्ली में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा : देवेन्द्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आली गांव में मकानों पर कार्रवाई को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने इसे गरीबों को राजधानी से बेदखल करने की कोशिश बताया। उन्होंने सवाल किया कि उजाड़े जाने के बाद करीब 25 हजार लोग कहां जाएंगे। यादव आली गांव के शिव मंदिर पहुंचे और प्रभावित लोगों से मिले।

कांग्रेस के अनुसार, गांव में करीब 1800 से 2000 मकान कार्रवाई की जद में हैं। यादव ने कहा कि प्रभावितों को न तो वैकल्पिक आवास बताया गया है और न ही मुआवजे की घोषणा हुई है। उन्होंने भाजपा सरकार पर चुनाव वादों से मुकरने का आरोप लगाया। भाजपा ने जहां झुग्गी वहीं मकान नीति का वादा किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद गरीबों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस नेता ने मांग की कि आली गांव के लोगों को पुनर्वास के बिना न हटाया जाए।

वनडे के बाद टी20 में भी दबदबा कायम रखने उतरेगा भारत

» भारतीय टीम का वेस्टइंडीज से पहला टी20 मैच आज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम करने के बाद भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में दम दिखाने उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जानी है। सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ऐसे में नजरें इस बात पर होंगी कि क्या टीम इंडिया वनडे के बाद टी20 में भी अपना दबदबा कायम रख पाती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच साल 2009 से अब तक कुल 31 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारतीय टीम ने 20 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि वेस्टइंडीज को 10 मैचों में सफलता मिली है।

एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। यानी टी20 में भी कैरेबियाई टीम के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है। सरी ओर, वनडे सीरीज में भारत को कड़ी टक्कर देने के बाद वेस्टइंडीज टी20 में भी अपना दम दिखाना चाहेगी। कैरेबियाई टीम को शेरफेन रदफोर्ड, शिमरोन हेटमायर और रोमारियो शेफर्ड जैसे खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद

होगी। शाई होप ने वनडे में शानदार फॉर्म दिखाई थी और अब वह टी20 में भी उसी लय को बरकरार रखना चाहेंगे। बल्लेबाजों के साथ-साथ वेस्टइंडीज को अपने गेंदबाजों से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारतीय टीम हाल ही में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी है। टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी शानदार फॉर्म में हैं। ऐसे में दोनों आक्रामक बल्लेबाज वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। तिलक वर्मा भी अच्छी लय में हैं। उन्होंने एशियन गेम्स के



कुलदीप पर रहेंगी नजरें

टीम इंडिया के टी-20 एकादश में शामिल स्पिनर कुलदीप यादव पर सबकी नजर होगी। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले इन यादव ने गेंदबाज के लखनऊ के इकाना स्टेडियम में काफी क्रिकेट खेली है, जिसका उन्हें खासा अनुभव होगा। इकाना स्टेडियम में आठ साल पहले हुए टी-20 मुकाबले में कुलदीप यादव भारतीय टीम का हिस्सा थे। मुकाबले में उन्होंने दो अहम विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में टीम प्रबंधन उन्हें मौका देकर अजमा सकती है।

फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ महज 22 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए थे। ऐसे में मध्यक्रम में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए अहम साबित हो सकती है। हालांकि, भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव की कमी जरूर नजर आ रही है। तेज गेंदबाजी की कप्तान अर्शदीप सिंह संभालेंगे। उनका साथ देने के लिए प्रिंस यादव और मयंक यादव को टीम में चुना गया है।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, सरकार की नींद उड़ी

पैरामिलेट्री से पूरी दिल्ली में जगह-जगह बैरिकेडिंग राहुल-प्रियंका को हिरासत में लेकर किया रिहा

» विरोध प्रदर्शन में 19 दलों के नेता हुए शामिल

» सपा कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का चुनाव आयोग पर हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग तक विरोध-प्रदर्शन करने निकला है लेकिन पुलिस ने उनको बीच में ही रोक लिया। विपक्ष के साथ हजारों की भीड़ भी साथ में थी। भीड़ को देखकर मोदी सरकार की नींद उड़ गई। जगह-जगह पैरा मिलेट्री फोर्स लगा दी गई थी। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में 19 दलों के नेता शामिल हैं।

हालांकि आम आदमी पार्टी और डीएमके इसमें शामिल नहीं हैं। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा को पुलिस ने कुछ देर के लिए हिरासत में लिया। हालांकि, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

जब हमारे लोग देश के लिए जान दे सकते हैं तो हम जेल क्यों नहीं जा सकते : खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम लोकतंत्र फिर से बहाल करने के लिए विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारे लोग देश के लिए जान दे सकते हैं तो हम जेल क्यों नहीं जा सकते। खरगे ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। बता दें कि 200 से ज्यादा सांसद एकसाथ लामबंद हैं। वह ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं।

सीजेपी नेताओं को पुलिस ने भेजे नोटिस, अभिजीत दीपके बोले- आंदोलन में न जाने का दबाव

कॉंग्रेस जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस नोटिस दिए जा रहे हैं और उन्हें आंदोलनों में शामिल नहीं होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यह दावा उन्होंने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले किया है। दीपके ने सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन महज एक नारा है और असली मंशा वन नेशन, वन पार्टी की है।



सड़क पर धरने पर बैठे राहुल-प्रियंका

विपक्ष सांसद भवन जाने की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस ने नीति आयोग के मुख्यालय के पास विपक्षी नेताओं को रोक दिया है। आगे नहीं बढ़ने देने पर राहुल और प्रियंका गांधी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। विपक्षी नेता ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। सपा नेता वैरिकेड पर चढ़ गए हैं। वहीं वे सभी नारेबाजी कर रहे हैं सपा सांसद भी बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।



सपा कार्यकर्ता संघर्ष से नहीं डरते : अखिलेश यादव

दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन में शामिल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सदस्य संघर्ष और मेहनत से कमी नहीं डरते। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए यहां पुलिस के बैरिकेड लगाए गए हैं। उन्होंने उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी पर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए बीजेपी को हराएगा।



बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश करते रहे विपक्षी सांसद

पुलिस के मार्च रोकते ही राहुल और प्रियंका धरने पर बैठ गए। सपा सांसद हाथों में तख्तीयां लिए हुए हैं, जिन पर लिखा है- बीजेपी ही CEC है। ये सांसद बैरिकेड लांघ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी सुरक्षाकर्मीयों को पीछे हटने के लिए कह रहे हैं। धरने पर बैठे अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में आम जनता को भरोसा है कि हमें चुनाव आयोग न्याय देगा और निष्पक्ष होगा। लेकिन यहां देखने को मिला है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है। सुल्तानपुर के नंदलाल निषाद के नकली दस्तखत करके वोट डाला जा रहा था और फॉर्म 7 भरवाया जा रहा था। इन लोगों ने पूरे बंगाल का चुनाव लूट लिया। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी दपतर एक ही तरह से काम कर रहा है। पीडीए के लोग मिलकर सविधान को बचाएंगे। पता चला है कि अदालत ने फॉर्म-6 को लेकर कहा है कि उनकी तरह से इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अखिलेश ने कहा कि स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा वरना हम लोग बैरिकेड तोड़कर आगे निकल जाते।

फैजुल्लागंज में जलकहर, 50 हजार घरों में घुसा पानी

3 लाख की आबादी बेहाल, राहत के नाम पर प्रशासन का कागजी खेल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। लखनऊ के उत्तरी छोर पर स्थित फैजुल्लागंज क्षेत्र में इस समय कुदरत के कहर से ज्यादा प्रशासनिक लापरवाही का पानी हिलोरे मार रहा है। क्षेत्र की मामा कॉलोनी, दाऊद नगर, प्रीति नगर और यश नगर समेत दर्जनों बस्तियां भीषण जलभराव की चपेट में हैं। आलम यह है कि करीब 50 हजार घरों के ड्राइंग रूम से लेकर रसोई तक में गंदा पानी तैर रहा है और लगभग 3 लाख की आबादी पिछले कई दिनों से इस टापू बन चुके इलाके में नारकीय जीवन जीने को मजबूर है।

घरों की पहली मंजिलें डूब चुकी हैं, चारपाई और राशन पानी में बह रहे हैं, और छतों पर तिरपाल ताने भूखे-प्यासे लोग टकटकी लगाए सिर्फ इस उम्मीद में आसमान निहार रहे हैं कि शायद कोई नाव उनकी तरफ आ जाए। बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है, पीने के साफ पानी की एक-एक बूंद के लिए हाहाकार मचा है और सीवर के गंदे पानी में जहरीले कीड़े-मकोड़े तैर रहे हैं।

स्मार्ट सिटी के नारों के बीच बदहाली का सच : हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई और जलनिकासी के नाम पर करोड़ों रुपये का बजट कागजों में खपा दिया जाता है, लेकिन बारिश आते ही फैजुल्लागंज की किस्मत में सिर्फ घुटनों से ऊपर



बदबूदार पानी और जहरीले संक्रामक रोगों का डर लिख दिया जाता है। बंधे के निर्माण और पंपिंग स्टेशनों के वादे सिर्फ चुनावी भाषणों में तैरते हैं। स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि चुनाव के समय हाथ जोड़ने वाले नेता और बड़े-बड़े दावों वाले अफसर आज इस मुश्किल घड़ी में उन्हें मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ चुके हैं। पानी भले ही आने वाले दिनों में उतर जाए, लेकिन सिस्टम की संवेदनहीनता और नाकामी का जो कीचड़ 3 लाख लोगों की जिंदगी पर लगा है, वह आसानी से नहीं धुलने वाला।

कागजी फाइलों में तैरती राहत, जमीन पर सन्नाटा

आबादी के इस संकट पर नगर निगम और जिला प्रशासन की मुस्तेदी का हाल यह है कि मदद की रफ्तार कछुए से भी धीमी है। 3 लाख की भारी आबादी के बीच राहत और बचाव कार्य केवल चंद मुख्य सड़कों तक सिमट कर रह गया है। जितनी मदद इस समय युद्धस्तर पर जमीन पर उतरनी चाहिए थी, उसका दसवां हिस्सा भी प्रभावित परिवारों तक नहीं पहुंच रहा है। वजह बिल्कुल साफ है कि अफसरों के लिए फैजुल्लागंज की बाढ़ एक मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि एयर-कंडीशनर कमरों में बैठकर %समीक्षा बैठकें निपटाने और फाइलों में आंकड़े चमकाने का वार्षिक जरिया बन चुकी है। प्रशासनिक मशीनरी की सुस्ती का आलम यह है कि दाऊद नगर और मामा कॉलोनी की तंग गलियों में राहत की इक्का-दुक्का सरकारी नाव पहुंची है। जहां हजारों परिवारों को तत्काल निकालने और भोजन-दवा पहुंचाने के लिए दर्जनों स्टीमर और एसडीआरएफ की टोलियों की जरूरत थी, वहां चंद राहत पैकेट बांटेकर इतिश्री कर ली गई। सोशल मीडिया पर अफसरों के निरीक्षण की तस्वीरें तो खूब चमक रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कैमरे की चमक खत्म होते ही अफसर अपनी गाड़ियां लेकर सूखे इलाकों की ओर लौट जाते हैं।

लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में लगी भीषण आग

» दो मजदूर झुलसे, दूर तक दिखा धुआं, फायर ब्रिगेड बुझाने में जुटी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट परिसर में मंगलवार सुबह करीब 6.30 बजे मजदूरों की लेबर कॉलोनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में लपटें और धुआं दूर से दिखाई देने लगा। हादसे के बाद मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के मुताबिक, एयरपोर्ट परिसर में टाटा प्रोजेक्ट्स की ओर से मजदूरों के रहने के लिए पीवीसी पैनल से तीन मंजिला आवास बनाया गया था। इसमें करीब 352 मजदूर रह रहे थे। बताया गया कि सुबह एक मजदूर सिलेंडर से खाना बना रहा था, तभी अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले

लिया। आग फैलने से पहले ही सभी मजदूरों को आवास से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि सामान निकालने की कोशिश में निर्मल और राहुल नाम के दो मजदूर झुलस गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही दमकल की नौ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशकत के बाद आग पर काबू पाया। आग से ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह जल गए, जबकि ऊपर के हिस्से भी प्रभावित हुए हैं।

थाना प्रभारी राजदेव प्रजापति के मुताबिक, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। एयरपोर्ट की सुरक्षा टीम के साथ सरोजनीनगर पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया और बड़ा जनहानि का हादसा टल गया।